

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग -2

देहरादून दिनांक : 06 दिसम्बर, 2010

विषय :- खेल निदेशालय के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2680/खेल निदे.भ.नि.पत्रा./2010-11-दे0दून, दिनांक- 8-10-के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि खेल निदेशालय निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-60/VI-1/2010-2 (12)/2006 दिनांक-31-3-2010 द्वारा रु0 150.23 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रु0 40.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रु0 110.23 लाख के सापेक्ष रु0 8.62 लाख मात्र की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार रु0 150.23 लाख के सापेक्ष रु0 48.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः अवशेष धनराशि रु0 101.61 लाख के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2010-11 में रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट से अधिक न किया जाय। किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा मितव्ययता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रक्योरमैट रूल-2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। 6

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरें मदों पर कदापि व्यय न की जाय। निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

5. जी.पी.डब्लू फार्म 09 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण बकाया से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। उक्त कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा विलम्ब की दशा में आगणन का पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार कार्यवाही हेतु शासनादेश के अनुरूप संस्था के साथ एमओयू की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय। कार्यों की गुणवत्ता के सम्बंध में थर्ड पार्टी की भी व्यवस्था की जायेगा, जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा।

6. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219 (2006) दिनांक-30-5-2006 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-475/XXVII (7)/2008 दिनांक-15 दिसम्बर, 2008 के द्वारा कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. किये जाने विषयक निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा-खेलकूद स्टेडियम-102- खेल स्टेडियम-08-खेल निदेशालय की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत मद के नामें डाला जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-699 (पी)/ XXVII-(3)/2010 दिनांक-30 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

/
(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 882 / VI-I / 2010-2(12) / 2006 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम लि० देहरादून।
3. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 6. एन०आई०सी०, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव

1